

tral Sector Scheme, is given in Statement II laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—342/71]

As regards the housing scheme for coal miners, no Central financial assistance is given to the State Governments and Union Territories. However, assistance is given to the managements of collieries out of Coal Mines Labour Welfare Fund. During 1970-71, Rs. 128.20 lakhs were paid to the managements by the Coal Mines Welfare Commissioner.

(c) and (d) Information relating to the number of houses sanctioned and completed during 1970-71, based on progress reports received so far from the State Governments in respect of the four State sector housing schemes and the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers is given in Statement III laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—342/71]

As regards the Housing Scheme for Coal Miners, against 6000 houses planned to be constructed by various Colliery managements during the year 1970-71, 4,180 houses were completed.

(e) Apart from the schemes mentioned above, all other Social Housing Schemes of this Ministry viz. Middle Income Group Housing Scheme, Land Acquisition and Development Scheme, and Rental Housing Scheme for State Government Employees are being continued during the current financial year, and will continue to remain in force during the remaining period of the Fourth Five Year Plan.

**नेहरू होम्योपैथिक कालेज, नई दिल्ली के विस्तार के लिये वित्तीय सहायता**

1470. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की डिफेंस कालोनी में स्थित नेहरू-होम्योपैथिक कालेज के विकास और विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने अनुदान और सहायता के रूप में कितनी धन राशि दी है;

(ख) भविष्य में इसके विकास और विस्तार के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिये इसे कितना अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ?

**निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :**  
(क) 1964 से 1970 तक के वर्षों में, इस कालेज को 3,14,000 रुपये दिये गये हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है कि उन्होंने इसके विकास के लिये कोई योजना नहीं बनाई है ।

भारत सरकार उप स्नातक होम्योपैथिक शिक्षा के वर्तमान स्तर में सुधार कर उसका विकास करने के लिये आर्थिक सहायता देने की एक योजना पर विचार कर रही है । इसन व्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख रु० देने के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है ।

**होम्योपैथी अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना**

1471. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होम्योपैथी अनुसन्धान केन्द्र के स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएंगे तथा उनपर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० खट्टोपाध्याय) :**  
(क) और (ख) भारतीय चिकित्सा और